

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 2/24

GCMS NO 2024/17

रामलाल पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी हलोन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
अपीलांत

बनाम

1. प्रेमा पुत्र ग्यारसा जाति बैरवा निवासी हलौन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. विनोद पुत्र घनश्याम जाति बैरवा निवासी हलौन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. पूजा पुत्री स्व0घनश्याम पत्नि चिरंजीलाल जाति बैरवा निवासी हलोन्दा हाल निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4. लक्ष्मी पुत्री स्व0घनश्याम पत्नि मन्नू जाति बैरवा निवासी हलौन्दा हाल निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. सुगना पत्नि स्व0घनश्याम जाति बैरवा निवासी हलोन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7. उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रेसपो0

अपील संख्या - 50/24

GCMS NO 2024/86

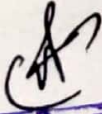
1. चिरंजीलाल पुत्र स्व0कोरीलाल बैरवा
2. हीरालाल बैरवा
3. चन्द्रप्रकाश बैरवा
4. प्रभूलाल बैरवा
5. राजाराम बैरवा
6. घनपाल बैरवा
7. बेवा नारायणी पत्नि स्व0 रामफूल बैरवा
8. मीरादेवी पुत्री स्व0रामफूल बैरवा
9. रामेश्वर बैरवा पुत्र स्व0रामफूल बैरवा
10. सम्पत बैरवा पुत्री स्व0रामफूल बैरवा

महावीर पुत्र स्व0रामफूल बैरवा निवासीयान ग्राम हलौदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
अपीलांत

बनाम

1. कालू पुत्र गोविन्दा बैरवा निवासी हलौदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. हैण्ड होल्डर तहसीलदार जरिये तहसील सवाई माधोपुर
3. उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

रेसपो0


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



दोनो अपील विरुद्ध मु०नं० 119/15 निर्णय दिनांक 24.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला० श्री घनश्याम जाट

अभिभाषक रैस्प० कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक 24.02.2025

निर्णय

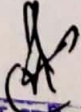
प्रस्तुत दोनो अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.11.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है।

दोनो अपीले एक ही आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। प्रस्तुत दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में मौती पुत्र जन्सी वगै० जातियान बैरवा निवासीयान हलोन्दा तहसील व जिला सवाई माधोपुर ने एक वाद पत्र सन 2005 में अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादीगण ग्राम हलोदा के काश्कार पेशा व्यक्ति है। पूर्व में वादीगण ग्राम बलरिया सुनारी ऐण्डा वगै० से सम्बन्धित 2010 में आकर आबाद हुए थे तथा वादीगण के बुजुर्ग पटेलाल, ग्यारसा, छीतर, कवरया बैरवान को यह भूमि ग्राम हलोदा में ठीकाना श्री राव बहादुरजी राजा मानसिंह जी ठीकाना बरवाडा द्वारा समस्त चमारान को यह जमीन खेती के वास्ते उनके ठीकाने में वाके होने के कारण काश्त हेतु दी गई थी जिसकी तहशीर राजासाहब द्वारा दिनांक 3.8.54 को उनके कारिन्दे री गुलाब चंद जैन अहलकार ठीकाना बरवाडा लिखाई जाकर दस्खस्त करके पटेलान को सुपुर्द की गई तब से वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही इस आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे हैं। आराजीयात को उनके कब्जे के मुताबिक एवं वाद में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 15.10.55 को प्रभाव में आने के बाद एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटन की कार्यवाही प्रत्येक व्यक्ति को 15 बीघा भूमि आवंटन कर उनको दे दी गई उस समय तत्कालीन पटवारी हल्का नजीर अली के द्वारा यह जमीन मौके पर संभलवाई गई। इस आराजीयात को बाद में वादीगण की खातेदारी अधिकार देकर खातेदारी दर्ज कर दी गई और भूमि पर बतौर खातेदारान वादीगण के नाम दर्ज हो गये। जो जमाबंदी सम्बन्धित 2041 से 2044 में दर्ज है। गत सेटलमेंट वर्ष 1999 में किया गया उसमें अमीन द्वारा वादीगण को आराजीयात का रकबा मुताबिक आदेश क्रमांक 282 एस ओ टोंक दिनांक 19.2.99 कम कर दिया गया और इसी आदेश से ख०न० 98,113,117,119,123,125,126,127,134 के रकबे में कमी कर दी गई। वादीगण की उपरोक्त आराजीयात ख०न० में से जो रकबा कम किया गया है वह रकबा 589 बीघा 9 विस्वा सिवायचक किया जा चुका है। जो सेटलमेंट विभाग द्वारा मनमाने तरीके से गलत तरीके से कम किया गया है तथा आदेश क्रमांक 282 दिनांक 19.2.99 एस ओ टोंक द्वारा पारित आदेश क्रमांक 13/227 राजस्थान/गुप/1/93 दिनांक 23.5.94 राजस्थान सरकार द्वारा प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) के द्वारा पारित आदेश की रोशनी में स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि इस आदेशानुसार प्रत्येक काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार देने का आदेश पारित किया गया है इस आदेश से प्रत्येक सहखातेदार अर्थात् वादीगण की खातेदारी बदस्तूर रखी जानी थी वैसे भी प्रतिवादीगण को इस आराजी का रकबा कम करने का कोई अधिकार




राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नहीं था। सेटलमेंट विभाग को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण जिनका रकबा कम किया गया है वह आराजी ख0न0 125,126,127 ग्राम हलोन्दा के काश्तकार खातेदार हैं। जिनका रकबा कम करना या सिवायचक दर्ज करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक काश्तकार की प्रस्तुत जमाबंदी में दर्ज आराजीयात जिसमें 15 बीघा प्रत्येक व्यक्ति के नाम दर्ज कर उस आराजी को घटाने अथवा बढ़ाने एवं उसका स्थान तब्दील करने का कोई अधिकार सेटलमेंट विभाग/प्रतिवादी को नहीं था। सेटलमेंट विभाग द्वारा अनुचित रूप से वादीगण की आराजीयात की मौका स्थिति तब्दील कर दी गई नवीन नम्बरान इस प्रकार बनाये गये कि प्रत्येक काश्तकार खातेदार को अपनी मौके की स्थिति से हटकर दूसरे स्थान पर कब्जा प्राप्त करना पड़ेगा और पूरे गांव के काश्तकार को एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे बाजी में फंसना पड़ेगा। क्योंकि आज जिस स्थिति में जो खातेदारान काबिज हैं उनकी उसी स्थिति में वही पर उसी खसरा न0 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जानी चाहिए जो नहीं की गई है। वादीगण भौतिक रूप से मौके पर काबिज काश्त हैं उनकी भूमि को सिवायचक मानकर प्रतिवादीगण द्वारा बेदखली की कार्यवाही कर दी जाती है तो उनके वैधानिक अधिकार समाप्त हो जावेगे और उनको जीवनभर मुकदमे में फंसना पड़ेगा। इसके लिए न्यायसंगत है कि राजस्व रिकार्ड में इस आशय की दुरुस्ती की जावे तथा बतौर खातेदार उनका नाम उक्त ख0न0 में उनके खाते के मुताबिक दुरुस्ती की जावे। उक्त गलत इन्द्राज को सही कराने बाबत वादीगण द्वारा उच्चाधिकारियों को कई बार निवेदन किया जा चुका है परन्तु किसी प्रकार की कोई दुरुस्ती नहीं हो पाई है। इस प्रकार यह भूमि जो प्रत्येक काश्तकार के खाते एवं कब्जे में है उसको उसी खाते की मुताबिक तरमीम करके जो काश्तकार जहाँ काबिज हैं उसी स्थान पर उसके खातेदारी के इन्द्राज राजस्व जमाबंदी व ट्रेस में किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं कर गलत तरमीम कर रकबा कम करके वादीगण को खातेदारी अधिकार से वंचित कर दिया जो प्रत्येक काश्तकार को अनुचित है। वादीगण को यह अधिकार है कि वह अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर मुताबिक संलग्न जमाबंदियां इस आशय की करावे कि वह विवादित भूमि वार्के ग्राम हलोन्दा के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी सेटलमेंट विभाग व तहसीलदार को इस आशय की दुरुस्ती कराने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह आराजीयात की खातेदारी उनके नाम राजस्व जमाबंदी में बदस्तूर साबित करे तथा आराजीयात को सिवायचक रकबे के इन्द्राज को समाप्त करे तथा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करे जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक प्रभावित नहीं हो। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 37/15 मौती बनाम सरकार पेश की गई थी। जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.9.15 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.3.15 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि समस्त वादीगण से तथा वन विभाग से भी साक्ष्य सबूत लेकर मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई जाकर तथा उभयपक्ष को


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में विधि अनुसार पालना की जाकर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बाबजूद तामिल रेस्पों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बहस अपीलांत अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपील संख्या 2/2024

अपीलांत के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विसंगति पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट की रिपोर्ट की असहमति व्यक्त की गई है परन्तु फिर भी अपने निर्णय में सेटलमेंट की सूची दिनांक 27.11.14 को आदेश का अंश बनाकर अहम भूल की है। सेटलमेंट की रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 न तो सही है और न ही सम्पूर्ण है। उक्त सेटलमेंट रिपोर्ट को न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया जा चुका है। फिर भी उसको आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण 213 थे जिनमें अपीलांत का क्रम संख्या 104 पर रहा है। अपीलांत को 15 बीघा भूमि आवंटन हुई उसका ख०न० 127/1 क्षेत्रफल 15 बीघा अपीलांत को भूमि आवंटन हुई। जब से ही आवंटित भूमि पर अपीलांत का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांत के कब्जे की भूमि का सेटलमेंट सर्वे रामनिवास घनश्याम प्रेमा रेस्पों का नाम होने से रेस्पों संख्या 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया। जबकि रेस्पों संख्या 1 ता 5 का मौके पर भूमि ख०न० 1377 रकबा 1.20 है० पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान में भी कब्जा नहीं है। उनका अन्य आराजीयात पर कब्जा है। परन्तु रेस्पों संख्या 6 द्वारा मौके की जाँच किये बिना ही रेस्पों संख्या 1 व मृतक घनश्याम के वारिस रेस्पों संख्या 2 ता 5 व मृतक रामनिवास जो अविवाहित जिसकी मृत्यु दिनांक 4.1.87 को हो चुकी थी उसके वारिसान की जाँच किये बिना खोजा है जो गलत है एवं निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.3.15 के विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा में अपील संख्या 37/15 उनवानी मोती वगै० बनाम उप जिला कलेक्टर पेश की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 30.9.15 को किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए वादीगण/अपीलांत से तथा वन विभाग से साक्ष्य सबूत एवं मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर वादीगण एवं अपीलांत की उपस्थिति में साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो दोबारा मौके पर वास्तविक स्थिति जो व्यक्ति जहाँ काबिज है उसकी रिपोर्ट मंगवाई और पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया गया। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ


राजस्व अपील प्राधिकारी
सुवाई माधोपुर

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रेस्पोंडेंस संख्या 6 को ही अपने निर्णय से उपर रखकर विवादों का निस्तारण करना चाहा है जो विधि विरुद्ध है। निर्णय सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को ही महत्व देकर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्रशासन गांवों के संग अभियान में बिना ग्रामवासियों को सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया है तथा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थी को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के आवंटन के समय से ही कब्जे शुदा भूमि को रेस्पोंडेंस प्रेमा, स्वधनश्याम एवं स्वधननिवास के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत लगा दी गई है। घनश्याम की मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान रिकार्ड पर है रामनिवास अविवाहित मर चुका है। रेस्पोंडेंस का कब्जा अन्य आराजीयात पर है एवं रिकार्ड में अपीलार्थी की आराजी खनन 1377 रकबा 1.20 है का इन्द्राज होना है। इसी कारण यह अपील पेश करनी आवश्यक हुई। अपीलार्थी का आवंटन के समय से ही खनन 1377 रकबा 1.20 है पर कब्जा है जो सेटलमेंट की गलती से रेस्पोंडेंस संख्या 1 ता 5 के नाम लग गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का आदेश दे रखा है परन्तु सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर अहम भूल की है ऐसी स्थिति में निर्णय सेटलमेंट रिपोर्ट 27.11.14 सहित निरस्त योग्य है। सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट 27.11.14 एवं इससे पूर्व बनाई गई सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट दिनांक 31.8.12 दोनों ही एक दुसरे की कॉपी है कोई अन्तर या परिवर्तन नहीं है इसलिए रिपोर्ट को निर्णय का बेस बनाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। मूल दावे में अपीलार्थी आवंटन के समय से ही कब्जे की आराजी खनन 1377 रकबा 1.20 है की हद तक अपील पेश कर रहा है। इसी आधार पर रेस्पोंडेंस बनाये गये हैं। जो ही आवश्यक पक्षकार है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलार्थी लगातार कभी पटवारी कभी गिरदावर व कभी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन करता रहा परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिये जाते एवं प्रेमा व मृतक घनश्याम की विरासत का नामा संख्या 227 गलत खोल कर स्पष्ट कर दिया कि रेस्पोंडेंस संख्या 6 निर्णय की पालना नहीं कर रहे हैं। इसके बाबजूद न्यायालय हाजा में अपील पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील क्षेत्राधिकार के अभाव में एडमिशन पर दिनांक 27.2.23 को खारिज कर दी गई। जिसके संबंध में संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहाँ चाराजोही करने पर संभागीय आयुक्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील संभागीय आयुक्त के यहाँ पोषनीय नहीं होकर न्यायालय हाजा में पोषनीय होना निर्देशित किया गया। जिसके बाबत अति संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहाँ चाराजोही करने पर उनके द्वारा अपील मूल ही लौटाई जाकर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इस कारण प्रोपर समय पर अपील न्यायालय हाजा में पेश नहीं हो सकी। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से अपील के साथ संलग्न कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.21 व सेटलमेंट सर्वे रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को तथा गलत रूप से खोला गया नामा संख्या 227 दिनांक 12.9.22 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के पुराने नम्बर खतौनी संख्या 116 के खसरा नं 127/1 रकबा 15 बीघा जिसके नवीन नम्बर 1377 रकबा 1.20 है वाके ग्राम




राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हलोन्दा तहसील सवाई माधोपुर पर आवंटन के समय से पूर्व खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2041-2044 को आधार मानते हुए आवंटन के समय से खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कृपा करे।

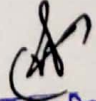
अपील संख्या 50/24

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विसंगति पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सेटलमेंट की रिपोर्ट की असहमति व्यक्त की गई है परन्तु फिर भी अपने निर्णय मे सेटलमेंट की सूची दिनांक 27.11.14 को आदेश का अंश बनाकर अहम भूल की है। सेटलमेंट की रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 न तो सही है और न ही सम्पूर्ण है। उक्त सेटलमेंट रिपोर्ट को न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया जा चुका है। फिर भी उसको आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे वादीगण 213 थे जिनमे अपीलांट का क्रम संख्या 31 पर रहा व अपीलांट संख्या 2 लगायत 6 का पिता स्व0गोपाल का नाम क्रम संख्या 29 पर व अपीलांट संख्या 7 ता 11 के पिता स्व0रामफूल का नाम क्रम संख्या 30 पर था। अपीलांटान के पिता कोरीलाल पुत्र भोलू उर्फ मोडू को भूमि ख0न0 74/2 रकबा 15 बीघा अपीलांटान के पिता स्व0कोरीलाल को आवंटित हुई जब से आवंटन भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.3.15 के विरुद्ध न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 37/15 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 30.9.15 को न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की जाकर वादीगण एवं अपीलांट तथा वन विभाग से साक्ष्य सबूत एवं मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर वादीगण एवं अपीलांटान की उपस्थिति मे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पुनः मौके की वास्तविक स्थिति जो व्यक्ति जहाँ अपनी भूमि पर काश्त है उसकी रिपोर्ट मंगवाई और पूर्व की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को आधार बनाकर पुनः निर्णय पारित कर अहम भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट द्वारा उच्चाधिकारियो को शिकायत करने के उपरान्त भी रेस्प0 संख्या 2 द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से अपीलांट की भूमि ख0न0 1532 का नामा0 रेस्प0 संख्या 1 के नाम खोलकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया है जो गलत है। भूमि ख0न0 1532 पर रेस्प0 संख्या 1 का कब्जा ना तो पूर्व मे था ना ही वर्तमान मे है। क्योकि रेस्प0 संख्या 2 ने सर्वे सूची दिनांक 27.11.14 तैयार की। उस सूची को माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 37/15 दिनांक 30.9.15 को निरस्त किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे रेस्प0 संख्या 2 को अपने से उपर रखकर विवादो का निस्तारण करना चाहा है जो विधि विरुद्ध है। निर्णय मे सर्वे दिनांक 27.11.14 को महत्व देकर कानूनी भूल की है। रेस्प0 संख्या 2 द्वारा अपनी तरफ से कोई जाँच न करके पूर्व सर्वे सूची की नकल कर दूसरी सूची सर्वे तैयार इसी रिपोर्ट को मान लिया है। जो निरस्त योग्य है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय प्रशासन गांवों के संग में निर्णित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर ग्रामवासियों को नहीं दिया गया तथा व्यक्तिगत रूप से अपीलान्त को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध होने से निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण 213 पक्षकार थे जिनमें अपीलान्त संख्या 1 अपीलान्त संख्या 2 ता 6 का पिता स्व० गोपा का नाम 29 व अपीलान्त संख्या 7 ता 11 के पिता पति का नाम कम संख्या 30 पर है। इस भूमि में अपीलान्त अपने बुजुर्गों के समय से ही काबिज थे। भूमि ख०न० 1532 रकबा 0.4400 को रेस्प० संख्या 1 के नाम रेस्प० संख्या तीन के द्वारा बिना मौके की जाँच किये ही रेस्प० संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड का नामा० गलत खोला है। जबकि रेस्प० का कब्जा उक्त नम्बर पर कभी नहीं रहा। उसका कब्जा अन्य आराजीयात पर है। अपीलान्त का आवंटन के समय से ही कब्जा ख०न० 1532 रकबा 0.4400 है० पर है जो सेटलमेंट की गलती से रेस्प० संख्या 1 के नाम लग गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का आदेश दिया है परन्तु सेटलमेंट रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को आधार बनाकर अहम भूल की है। ऐसी स्थिति में निर्णय सेटलमेंट रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 सहित निरस्त योग्य है। सेटलमेंट रिपोर्ट एवं इससे पूर्व बनाई गई सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट 31.8.12 दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं कोई अन्तर या परिवर्तन नहीं है। इसलिए सेटलमेंट रिपोर्ट को निर्णय का बेस बनाकर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 को अपीलिय न्यायालय निरस्त कर चुका है जिसमें एक आधार यह भी था कि सेटलमेंट रिपोर्ट की गलती है परन्तु उसी को आधार मानकर निर्णय देना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलान्त लगातार कभी पटवारी कभी गिरदावर व कभी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन करता रहा परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिये जाने एवं दिनांक 22.6.22 को रेस्प० संख्या 1 के नाम नामा० संख्या 219 गलत रूप से खोलने से स्पष्ट कर दिया है। इस कारण माननीय न्यायालय में अपील करने में देरी हुई है। जो अपीलान्त की सदभावी भूल है। फिर भी मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील में साथ संलग्न है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.21 व सर्वे रिपोर्ट दिनांक 27.11.14 तथा रेस्प० संख्या 1 के पक्ष में खोला गया नामा० संख्या 219 को अपीलान्त के कब्जे की भूमि की हद तक निरस्त कर अपीलान्त पुराना ख०न० 74/2 रकबा 15 बीघा नवीन ख०न० 1532 रकबा 0.4400 है० वाके ग्राम हलोदा को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कृपा करे। रेस्प० संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अपीलान्त के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही अपने प्रतिनिधी से करावे।

अपीलान्त अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्रामवारिसान हलौदा द्वारा एक साथ 213 वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने पर उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 37/15


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दायर की गई थी। जिस पर इस न्यायालय द्वारा 30.9.15 को अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण वन विभाग से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। पत्रावली में अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि ग्राम हलोदा की भूमि के लिए वाद पत्र धारा 88 व 188 का पेश किया गया था। जिसके अनुसार सेटलमेंट विभाग के पत्र क्रमांक 282 एस आरे टोक दिनांक 19.2.99 के आदेश से रकबा 589 बीघा 9 विस्वा को सिवायचक दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट/वादीगण का कथन रहा कि ग्राम हलोदा की भूमि हमारे पूर्वजों को ठिकाना श्री राव बहादुरजी राजा मानसिंह के समय से बैरवान जाति को खेती के लिए दी गई थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर आवंटन कर दी गई। तब से भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि का रकबा कम किये जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने के कारण वाद पत्र पेश किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि वन विभाग एवं वादीगण/अपीलांटान से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रकरण नियत कर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली को अभियान में नियुक्त करने से पूर्व विधि के प्रावधानों के तहत वादीगण को जरिये न्यायालय सूचित किया जाना चाहिए था। इसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र वादीगण के पक्ष में तो निर्णित किया गया है परन्तु निर्णय की पालना नहीं होने के कारण एवं कब्जे अनुसार पालना नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट द्वारा पुनः अपील पेश की गई है। यदि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना अक्षरक्ष नहीं होती है तो अन्य वादीगण द्वारा अपीले इस न्यायालय में पेश किये जाने की संभावना प्रतीत होती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.9.15 के अनुसार प्रकरण में पुनः वादीगण/अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट इस अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में आपके निर्णय दिनांक 24.11.21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए अपीलांटान की आराजीयात ख0न0 1377 रकबा 1.20 है0 एवं ख0न0 1532 रकबा 0.5700 है0 ग्राम हलोदा की हद तक अपीलांटान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त आराजीयात ख0न0 1377 व 1532 के मौके की कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांटान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में दिनांक 09.4.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कर्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी